

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 623/16

सन् 2016

आरसीएमएस संख्या 2016/00340

बउनवानी:-चतुर्भुज पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी बौली, तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर  
बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बौली

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बौली की मिसल संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक  
7.11.2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री राधेश्याम वैष्णव  
2. श्री महावीर चौधरी

वकील अपीलान्त  
पैरोकार राजस्व

:- निर्णय :-

दिनांक 17.6.2019

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार बौली की मिसल संख्या 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 7.11.2016 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि 18.10.2016 को आम जनता ग्राम बौली की ओर से अपीलान्त द्वारा ख0न0 1676 सिवायचक पर अतिक्रमण कर आम रास्ते में अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार बौली के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर प्राप्त शिकायत पर पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गयी है। तहसीलदार बौली द्वारा अपीलान्त को पत्रांक/राजस्व/16/2660 दिनांक 24.10.2016 से नोटिस जारी कर दिनांक 27.10.2016 को उपस्थित होकर उक्त अतिक्रमण क्यो नही हटाने बाबत साक्ष्य सबूत पेश करने का लिखा गया अपीलान्त द्वारा नोटिस की पुस्त पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटाने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ ओर ना ही नोटिस का जवाब पेश किया। अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु दिनांक 7.11.2016 तक का समय पुनः दिया गया। किन्तु अपीलान्त द्वारा दिनांक 7.11.2016 तक अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नही की गयी ना ही कोई सबूत पेश किया गया। इस प्रकार अपीलान्त को पूर्ण सुनवायी व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने के बाद आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जांच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नही किया कि अपीलान्त का किस ग्राम में किस ख.न. पर कितने रकबे पर किस जगह क्या अतिक्रमण है तथा किस सम्वत् मे श्यालू या उन्हालू मे अतिचार किया है। अपने आदेश में कही भी अंकित नही किया गया है जो निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवायी को कोई नोटिस नही दिया तथा सुनवायी का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मे आदेश जैर अपील पारित कर दिया है। यह कथन भी किया कि पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध मे भी कोई साक्ष्य सबूत नही होते हुए भी अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपना आदेश गलत तरीके से पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 3.1.2017 के अनुसार अपीलान्त के साथ-साथ अन्य 7 व्यक्तियों का अतिक्रमण है जिसमे शिकायत कर्ता के


पिता का नाम भी है जब इतने व्यक्तियों का अतिक्रमण है तो केवल अपीलान्त को ही इतनी कठोर सजा क्यों दी गयी है कानून सभी के लिए समान है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया ।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि 18.10.2016 को आम जनता ग्राम बाँली की ओर से अपीलान्त द्वारा ख0न0 1676 सिवायचक पर अतिक्रमण कर आम रास्ते में अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार बाँली के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर प्राप्त शिकायत पर पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गयी है। तहसीलदार बाँली द्वारा अपीलान्त को पत्रांक/राजस्व/16/2660 दिनांक 24.10.2016 से नोटिस जारी कर दिनांक 27.10.2016 को उपस्थित होकर उक्त अतिक्रमण क्यों नहीं हटाने बाबत साक्ष्य सबूत पेश करने का लिखा गया अपीलान्त द्वारा नोटिस की पुस्त पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटाने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ ओर ना ही नोटिस का जवाब पेश किया। अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु दिनांक 7.11.2016 तक का समय पुनः दिया गया। किन्तु अपीलान्त द्वारा दिनांक 7.11.2016 तक अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी ना ही कोई सबूत पेश किया गया। इस प्रकार अपीलान्त को पूर्ण सुनवायी व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने के बाद आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त को जारी नोटिस की पुस्त पर अपीलान्त द्वारा नोटिस में अंकित दिनांक 27.10.2016 तक अतिक्रमण हटा लेने तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समय चाहा गया नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 7.11.2016 को उपस्थित होने का मौका दिया गया। किन्तु अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की गयी भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्त का अतिचार साबित नहीं होता हो ओर ना ही अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बाँली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर दिनांक 3.1.2017 को भी 0.1 है0 पर बाडा व छाणपोस बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(डॉ0एस0पी0सिंह)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

